प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

<u>जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की समस्याओं का मैट्रिक्स और सुझाए गए समाधान</u>

#	जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की समस्याएं-	वेबिनार प्रतिभागियों द्वारा सुझाए गए समाधान-
1.	पीएम जन धन योजना के अनुमानित 23% खाते महिलाओं और अन्य लाभार्थियों के लिए मासिक पूर्व अनुदान राशि लेने के लिए एक्सेस करना मुश्किल हैं।	आरबीआई विशेष रूप से पीएमजेडीवाई बैंक खातों की परेशानी मुक्त पुनर्सक्रियन के लिए एक परिपत्र जारी कर सकता है लाभार्थियों के लिए, जो डाकघर के कर्मचारियों के माध्यम से अनुग्रह राशि के लिए अपने घर के बाहर पात्र हो और राशि वितरण की अवधि के लिए निश्चित स्थान बैंकिंग संवाददाताओं को इटंरनेट बैंक मित्र में बदले। उन्हें COVID-19 संबंधित एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है
2.	पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत घोषित पीएम उज्जवला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडरों तक पहुंच पर कोई स्पष्टता नहीं हैं । लॉकडाउन प्रवर्तन के कारण, लाभार्थी एलपीजी आपूर्तिकर्ता एजेंसी को भुगतान करने के लिए अपने बैंक खातों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे	GoI परिपत्र जारी करके स्पष्ट कर सकती है कि लाभार्थियों द्वारा मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। COVID-19 संबंधित एहतियाती उपायों को पालन करते हुए , लाभार्थियों के DBT लाभ के लिए इटीनरेंट बैंक मित्रो की मदद ली जा सकती है
3.	लॉकडाउन प्रवर्तन के कारण, एलपीजी आपूर्तिकर्ता एजेंसियां कई जगहों पर इस बात पर जोर दे रही हैं कि उपभोक्ता ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर रिफिल लेने के लिए अपने प्रतिष्ठानों पर जाएं।	OMCs अपनी आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को बुकिंग प्राप्त करने पर घर के दरवाजे पर गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर सकता है, COVID-19 संबंधित एहतियाती उपायों का पालन करते हुए।
4.	जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की आवाजाही के बारे में मैक्रो स्तर की जानकारी है, जिला, उप-जिला और वार्ड स्तरों पर स्टॉक की खरीद या बिक्री के बारे में बहुत कम पारदर्शिता है।	जिला प्रशासन को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के "स्पष्टीकरण" के तहत उल्लिखित प्रसार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से एक साप्ताहिक आधार पर लाभार्थियों को पीडीएस आपूर्ति और वितरण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए (इंटरनेट, रेडियो के माध्यम से खुलासा,टीवी, समाचार पत्र, नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक पता प्रणाली और ड्रम की बीट का उपयोग करते हुए अन्य प्रकार की घोषणाएं) दूरदर्शन के देशव्यापी आउटरीच का उपयोग पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज के कार्यान्वयन के तरीके और स्थिति के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए किया जाना चाहिए।

5.	जिला और उप-जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुँच मुश्किल हो रही है। अधिकांश राज्य सूचना आयोग बंद हो गए हैं और स्थानीय शहरों और शहरों के बाहर भेजे जाने वाले सतह मेल को स्वीकार करने के लिए डाकघरों को बंद करने के कारण आरटीआई आवेदन असंभव हो गए हैं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) सभी राज्य सरकारों को सलाह जारी कर सकता है कि वे संबंधित राज्य सूचना आयोगों से आग्रह करें कि वे केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों के साथ काम फिर से शुरू करें।
6.	राज्यों में पीएम गरीब कल्याण राहत पैकेज के कार्यान्वयन के संदर्भ में भ्रष्टाचार के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं	आम जनता से भ्रष्टाचार की शिकायतों को स्वीकार करने और पूछताछ करने के लिए संबंधित लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से आग्रह करने के लिए DoPT राज्य सरकारों को सलाह जारी कर सकता है। जनता से संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी निकायों को भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने और आगे बढ़ाने के लिए हर राज्य में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित की जा सकती है। इन नंबरों को व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाना चाहिए
7.	ओडिशा और अन्य स्थानों में नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और भ्रष्टाचार विरोधी अपराधियों को राहत वितरण में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पीटा जा रहा है	व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 को सभी राज्यों में तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सक्षम अधिकारियों को सूचित किया जाये ताकि वे व्हिसलब्लोअर हमलों और उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और पूछताछ करने जा सके। राज्य पुलिस को बिना किसी देरी के हमलों के ऐसे सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करने और दोषियों को बुक करने के लिए त्वरित जांच करने के लिए सलाह जारी की जानी चाहिए।
8.	राहत वितरण के मामले में राज्य सरकारों और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के बीच बहुत कम समन्वय है - चाहे पीएम गरीब कल्याण योजना या राज्य सरकार के स्वयं राहत पैकेज या स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई निजी पहल	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच राहत और पुनर्वास प्रयासों के समन्वय के लिए अधिकारियों के सशक्त समूह राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर स्थापित किए जाने चाहिए।
9.	शहरों, कस्बों और अन्य स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों को पीएम गरीब कल्याण योजना और अन्य राज्य कल्याणकारी उपायों के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड नहीं लाए हैं	सरकारी एजेंसियों को राहत और पुनर्वास उपायों के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभ पहुंचने के लिए पहचान प्रमाण के उत्पादन पर जोर नहीं देना चाहिए। पहचान और अधिवास की स्थिति की स्व-घोषणा को ऐसे लाभों तक पहुँचने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सभी राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को परिपत्र जारी किए जा सकते हैं

10.	विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। कुल जनसंख्या में से 8-10% के बीच उनमें से कई अपनी देखभाल करने वालों की सेवाओं का लाभ उठाने में, और पीएम गरीब कल्याण योजना और अन्य राहत के तहत उनके लिए आवश्यक वस्तुओं, जैसे भोजन, दूध, दवाइयों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं । सुनने की अक्षमता वाले लोग माननीय पीएम के भाषणों और विभिन्न अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि साइन लैंग्वेज व्याख्या उपलब्ध नहीं है।	लॉकडाउन पास को प्राथमिकता के आधार पर PwDs के लिए दैनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जारी किया जाना चाहिए। ऑडियो-विज़ुअल प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित किया जाना चाहिए और उनके लिए प्रसार करना चाहिए ताकि सामाजिक गड़बड़ी और अन्य एहतियाती उपायों को समझाया जा सके ताकि PwD कोरोना वायरस से बच सके । माननीय पीएम और दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित महत्वपूर्ण भाषणों के सभी टेलीकास्ट, टीवी स्क्रीन पर पर्याप्त रूप से दिखाई देने वाली सांकेतिक भाषा की व्याख्या के साथ वास्तविक समय में होने चाहिए।
11.	अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के दूरदराज के हिस्सों को इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल टेलीफोन द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है। वे मोबाइल फोन के माध्यम से शुरू की गई सेवाओं और एप्लिकेशन तक पहुंचने में असमर्थ हैं	यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग जहाँ मोबाइल फोन या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है,पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बिना किसी देरी के अपनी पात्रता प्राप्त कर सके ।
12.	अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों में कई दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को पीएम उज्जवला योजना द्वारा कवर नहीं किया गया है। जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलने वाली महिलाओं को अक्सर ऐसा करने से रोका जाता है या स्थानीय पुलिस द्वारा पिटाई की जाती है	पीएम उज्जवला योजना के तहत दूरदराज के बस्तियों और बस्तियों में रहने वाले परिवारों को अपने दरवाजे पर दैनिक उपयोग के लिए जलाऊ लकड़ी सहित पर्याप्त ईंधन स्रोतों से आपूर्ति की जानी चाहिए। वन विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी ऐसे घरों में ईंधन की आपूर्ति करने के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार लगे हो, COVID-19 संबंधित एहतियाती उपायों का पालन करते हुए ।
13.	जिला और तहसील स्तर के अधिकांश न्यायालयों और सांविधिक मानवाधिकार संस्थानों में तालाबंदी के कारण काम रुका हुआ है, लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्याय वितरण प्रणाली का उपयोग करने में असमर्थ हैं	लोगों को न्याय वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए निचली अदालतों को फिर से सक्रिय करने की तत्काल आवश्यकता है। राज्य, जिला और तहसील स्तरों पर वैधानिक कानूनी सेवा प्राधिकरणों को भी पुन: सक्रिय किया जाना चाहिए। कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध वकीलों के साथ-साथ उनके संपर्क नंबरों को विभिन्न जन मीडिया और अन्य ऑफ़लाइन तरीकों के माध्यम से व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाना चाहिए ताकि लोग प्रशासन की कार्रवाई और चूक के खिलाफ उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उनसे संपर्क कर सकें।

14.	COVID -19 ने निराशाजनक स्थिति और देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की तैयारियों की कमी का प्रदर्शन किया है। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और प्रवासी श्रमिकों के लिए बजटीय सहायता पर्याप्त नहीं है	सरकारों को स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और कल्याणकारी समूहों जैसे प्रवासी श्रमिकों के कल्याण पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना प्राथमिकता बन जाना चाहिए।